उत्तर उजाला

वर्ष 44 अंक 55 नैनीताल, बुधवार 13 जनवरी 2021 (पौष कृष्ण अमावस्या संवत् 2077) पृष्ठ 8 डाक पंजी. सं. यू.ए./नैनीताल/26/2021-2023

मूल्य 3.00 रु.

खुद ही प्रैक्टिस करके सीखा : नोरा – 5 निगेटिव आया साइना, प्रणय का परीक्षण – 7

तापमान	आज		कल संभावित	
शहर	अधि.	न्यू.	अधि.	न्यू.
दिल्ली	17	07	19	08
लखनऊ	18	06	19	06
नैनीताल	10	04	10	04
देहरादून	19	09	18	08
बरेली	15	08	17	07

सोना (10 ग्राम)	चांदी (प्र. किग्रा.)
48,946	65,380

रुपये की विनिमय दर	
पाउण्ड	99.75
यूरो	89.06
डालर (यूएस)	73.25
स्विस फ्रेंक	82.35
एमीरट्स-दरहम	19.94

कृषि कानूनों के अमल पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गतिरोध दूर करने के लिये गठित की समिति

- आन्दोलनरत किसानों से समिति के साथ सहयोग करने का अनुरोध
- नागरिकों की चिंता, समाधान चाहने वाले समिति से करेंगे बातचीत
- खालिस्तानियों की पैठ पर उच्चतम न्यायालय ने मांगा हलफनामा

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार और दिल्ली की सीमाओं पर धरना रहे रहे किसानों की यूनियनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने के इरादे से मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाने के साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिये चार सदस्यीय समिति गठित कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिये रोक लगा रही है और चार सदस्यीय समिति का गठन कर रही है। पीठ ने इस समिति के लिये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घन्वत, दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के नामों की घोषणा की। पीठ ने कहा कि इस बारे में विस्तृत आदेश पारित किया जायेगा। जिन तीन नये कृषि कानूनों को लेकर किसान आन्दोलन कर रहे हैं, वे कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार, कानून 2020, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून हैं। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी ताकत उसे इस तरह की समिति गठित करने से रोक नहीं सकती। साथ ही पीठ ने आन्दोलनरत किसान संगठनों से इस समिति के साथ सहयोग करने का अनुरोध भी किया। न्यायालय द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति में आन्दोलनरत किसान संगठनों के शामिल नहीं होने संबंधी खबरों के परिप्रेक्ष्य में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि जो वास्तव में इस समस्या का समाधान चाहते हैं वे समिति के साथ सहयोग करेंगे। पीठ ने कहा, हम देश के नागरिकों की जान-माल की हिफाजत को लेकर चिंतित हैं और इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान न्यायपालिका और राजनीति में अंतर को भी स्पष्ट किया और किसानों से कहा कि यह राजनीति नहीं है। न्यायालय ने साफ कहा कि किसानों को इस समिति के साथ सहयोग करना चाहिए। पीठ को जब यह सूचित किया गया कि उसके समक्ष एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें आन्दोलनरत किसानों को एक प्रतिबंधित संगठन के समर्थन का आरोप लगाया गया है, पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से इस बारे में जानकारी मांगी। वेणुगोपाल ने कहा कि किसानों के इस आन्दोलन में खालिस्तानियों ने पैठ बना ली है। इस पर पीठ ने उनसे कहा कि इस संबंध में हलफनामा दाखिल किया जाये। वेणुगोपाल ने कहा कि वह बुधवार तक ऐसा कर देंगे। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के माध्यम से केन्द्र द्वारा दायर एक आवेदन पर भी नोटिस जारी किया। इस आवेदन में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजन में व्यवधान डालने के लिये किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्राली मार्च या किसी अन्य तरह के विरोध-प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इस (शेष पृष्ठ 6 पर)

समिति के सदस्य

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घन्वत, दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी।

जारी रहेगा आंदोलन

किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया, लेकिन कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि कृषि कानूनों पर रोक लगाने के अदालत के आदेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कानून पूरी तरह वापस लिए जाएं।

समिति के सदस्य सरकार के समर्थक, पेश नहीं होंगे किसान

किसान संगठनों ने नहीं की समिति की मांग

संसद करे मामले पर चर्चा, 15 को सरकार के साथ होने वाली बैठक में होंगे शामिल

नयी दिल्ली। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने गतिरोध तोड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को मंगलवार को मान्यता नहीं दी और कहा कि वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति के सदस्य सरकार समर्थक हैं। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित समिति के सदस्य विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि वे लिखते रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हित में है। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान नेता ने कहा कि संगठनों ने कभी मांग नहीं की कि उच्चतम न्यायालय कानून पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करे और आरोप लगाया कि इसके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। उन्होंने कहा, हम सैद्धांतिक तौर पर समिति के खिलाफ हैं। प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए यह सरकार का तरीका है। किसान नेताओं ने कहा कि उच्चतम न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर कृषि कानूनों को वापस ले सकता है। एक अन्य किसान नेता दर्शन सिंह ने कहा कि वे किसी समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि संसद को मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम कोई बाहरी समिति नहीं चाहते हैं। बहरहाल किसान नेताओं ने कहा कि वे 15 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा (पंजाब) के उपाध्यक्ष लखबीर सिंह ने कहा कि समिति के विचार पर हमें विश्वास नहीं है और जब सरकार ने समिति के गठन का सुझाव दिया था, तभी से हम यह कहते रहे हैं, लेकिन इस बार उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है और हम इस समिति के कामकाज को देखेंगे। मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि संगठन शीर्ष अदालत की (शेष पृष्ठ 6 पर)

संक्षिप्त

मुरैना में जहरीली शराब पीने से 11 की मौत

मुरैना। मध्यप्रदेश में मुरैना जिले के दो गांवों में सोमवार रात को कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गयी और आठ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंगलवार को बताया कि जहरीली शराब पीने से मानपुर और पहवाली गांव के 12 लोगों की मौत हो गयी। बीमार लोगों को ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती लोगों के बयान लेने के बाद ही साफ हो पायेगा कि जहरीली शराब कहां से आई थी।

इंडोनेशिया में भूस्खलन 13 की मौत 26 लापता

जकार्ता। इंडोनेशिया के पश्चिम जावा प्रांत के एक गांव में भूस्खलन की दो घटनाओं के बाद 26 लोग लापता हो गए। बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। सिहानजुआंग में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण एजेंसी के प्रवक्ता रादित्य जाटी ने कहा कि बारिश के मौसम के कारण घटना स्थल के आसपास खोज और बचाव अभियान बाधित हुआ है। हाल के दिनों में भारी बारिश और उच्च ज्वार-भाटा के कारण इंडोनेशिया के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की दर्जनों घटनाएं हुई हैं और भयंकर बाढ़ आई है।

पेट चीर कर निकाली बच्ची, अब मिलेगी मौत

वॉशिंगटन। अमेरिका में इंसानियत को शर्मसार करने वाले अपराध की दोषी महिला कैदी को मौत की सजा देने की तैयारी पूरी हो गई है। अमेरिका के इतिहास में 67 साल बाद यह पहला मौका होगा जब किसी महिला कैदी को मौत की सजा दी जाएगी। इस महिला को जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के आठ दिन पहले ही मृत्युदंड दिया जाएगा। कैंसास की रहने वाली लीजा मोंटगोमेरी 16 दिसंबर 2004 को एक कुत्ते को गोद लेने के लिये लगभग 170 किलोमीटर दूर मिसूर कस्बे के स्किडमोर में 23 वर्षीय कुत्ता विक्रेता बॉबी जो स्टिनेट के घर गई। जहां उसने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने स्टिनेट का पेट चीरकर उससे बच्ची को निकाला और फरार हो गई।

खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.59 प्रतिशत पर

नयी दिल्ली। खाने का सामान सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में तेजी से घटकर 4.59 प्रतिशत रह गयी। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इससे पिछले महीने नवंबर में 6.93 प्रतिशत रही थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार खाद्य मुद्रस्फीति दिसंबर 2020 में घटकर 3.41 प्रतिशत रह गयी, जो एक महीने पहले 9.5 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है।

सात महीने में कोरोना के सबसे कम मामले

एक दिन में मिले 12,584 नए मरीज

मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.49 प्रतिशत, उपचाराधीन मरीजों की संख्या तीन लाख से कम

नयी दिल्ली। भारत में करीब सात महीने में 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे कम 12,584 नए मामले सामने आए और इसके साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,04,79,179 हो गए। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 167 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,51,327 हो गई। आंकड़ों के अनुसार कुल 1,01,11,294 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.49 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या तीन लाख से कम है। अभी कुल 2,16,558 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। यह कुल मामलों का 2.07 प्रतिशत है। भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, (शेष पृष्ठ 6 पर)

सड़क हादसे में घायल केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की सर्जरी

पणजी। कर्नाटक में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कल रात गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कई सर्जरी की गयीं। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्री की हालत स्थिर है। नाइक (68) की दोनों हाथों और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है। दुर्घटना में नाइक के साथ कार में सवार उनकी पत्नी विजया और एक सहायक की सोमवार को मौत हो गई। यह हादसा उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला के निकट हुआ जब मंत्री कर्नाटक में धर्मस्थल से गोवा लौट रहे थे। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय रक्षा राज्य और आयुष मंत्री नाइक को रात करीब 11 बजकर 10 मिनट पर गंभीर हालत में पणजी के निकट गोवा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल लाया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार रात कहा कि नाइक की हालत पहले गंभीर थी, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है।

वंशवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन

प्रधानमंत्री ने बताया–तानाशाही का एक नया रूप

- ऐसे लोगों में कानून के प्रति ना सम्मान और ना ही डर
- देश पर बढ़ाता है अक्षमता का बोझ : मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राजनीतिक वंशवाद पर कड़ा प्रहार किया और इसे लोकतंत्र में तानाशाही का एक नया रूप करार देते हुए कहा कि यह देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है।

वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वंशवाद की वजह से राजनीति में आगे बढ़े लोगों को लगता है कि उनके पहली की पीढ़ियों के भ्रष्टाचार का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा कि वे तो अपने घर में ही इस प्रकार के विकृत उदाहरण भी देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का कानून के प्रति ना सम्मान होता है ना ही उन्हें कानून का डर होता है। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने यह दावा किया कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं। उन्होंने राजनीति को सार्थक बदलाव का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का जहर इसी तरह लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा। पिछले छह वर्षों में देश की राजनीति में आए बदलावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और बिना किसी का नाम लिए कहा कि भ्रष्टाचार जिनकी विरासत थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है। ज्ञात हो कि वंशवाद की राजनीति के लिए भाजपा अक्सर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों पर हमले करती रही है। उन्होंने कहा कि यह देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है कि वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उबर नहीं पा रहे हैं। देश ईमानदारों को प्यार दे रहा है।

मोदी ने कहा कि इसके बावजूद कुछ बदलाव अभी भी बाकी हैं और इन बदलावों को लाने के लिए देश के युवाओं को आगे आना होगा। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वह है राजनीतिक वंशवाद। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका आचार, विचार और लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। राजनीतिक वंशवाद देश प्रथम के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार की भावना को मजबूत करता है। यह भारत में राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा कारण है। मोदी ने कहा कि इस स्थिति को बदलने का जिम्मा देश की युवा पीढ़ी पर है। उन्होंने कहा कि लेना और पाना छोड़, कुछ कर गुजरने के इरादे से जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का यह जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आपकी जिम्मेदारी (शेष पृष्ठ 6 पर)

कई राज्यों में पहुंची टीके की पहली खेप

16.5 लाख खुराक नि:शुल्क मुहैया करा रही भारत बायोटेक

कल तक सीरम इंस्टीट्यूट से 1.1 करोड़ और भारत बायोटेक से मिल जाएंगी 55 लाख खुराक

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि मंगलवार तक निर्धारित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय भंडारण केंद्रों तक कोविड-19 टीके की 54.72 लाख खुराक पहुंचा दी गयी है। 14 जनवरी तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1.1 करोड़ और भारत बायोटेक से 55 लाख खुराक मिल जाएगी।

कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के तहत 16 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान से चार दिन पहले मंगलवार को कोविशील्ड टीकों की खुराक पुणे से देश के 13 शहरों में भेजने की शुरुआत की गयी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक के अलावा भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की 55 लाख खुराक खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की 55 लाख खुराक खरीदी जा रही है। कोवैक्सीन की 38.5 लाख खुराक में से प्रत्येक पर 295 रुपये (कर को छोड़कर) की लागत आएगी। भारत बायोटेक 16.5 लाख खुराक नि:शुल्क मुहैया करा रही है, जिससे इसकी लागत प्रत्येक खुराक पर 206 रुपये आएगी। भूषण ने कहा कि चेन्नई, करनाल, कोलकाता और मुंबई में केंद्र सरकार के चार मेडिकल स्टोर डिपो हैं, जहां पर ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड की खुराक पहुंच चुकी है। इसके अलावा सभी राज्यों में कम से कम एक क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े राज्यों में कई (शेष पृष्ठ 6 पर)

गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक पल

पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने देश भर में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए कोविशील्ड टीके की आपूर्ति को मंगलवार को गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक पल करार दिया। इंस्टीट्यूट में कुछ पत्रकारों से बातचीत में पूनावाला ने कहा कि असली चुनौती टीके को आम जनता, संवेदनशील समूहों और स्वास्थ्यकर्मियों तक पहुंचाना है। वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और इससे जुड़े तमाम लोगों ने एक साल से भी कम समय में टीका विकसित करने में बहुत मेहनत की है।

कार्बेट से राजाजी भेजा गया बाघ बाड़े से गायब

ऋषिकेश। बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत हाल में कार्बेट बाघ अभयारण्य से राजाजी बाघ अभयारण्य स्थानांतरित किया गया पांच वर्षीय बाघ कहीं अन्यत्र चला गया है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मचने के साथ ही राजाजी पार्क के बाहरी क्षेत्र में बसी आबादी में दहशत फैल गई है। बाघ को स्थानांतरित कर आरटीआर की मोतीचूर रेंज के बाड़े में रखा गया था। उसके बाड़े में मौजूद न होने की जानकारी सोमवार शाम को मिली। वन कर्मी रेडियो कॉलर से निगरानी के आधार पर उसकी मौजूदगी का पता लगा रहे थे, लेकिन रेडियो कॉलर बाड़े में ही पड़ा मिला, जबकि बाघ वहां नहीं है। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने इस घटनाक्रम को परियोजना के लिए धक्का बताया और स्वीकार किया कि मौजूदा हालात में इस बाघ की निगरानी बहुत कठिन हो गई है। भरतरी ने बताया कि इस चुनौती से निपटने के लिए बाघ पुनर्वास की राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के आधार पर समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। आरटीआर सूत्रों ने बताया कि बाड़े से भागे बाघ को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी गयी है। इस घटना से आरटीआर के बाहरी क्षेत्र में बसी आबादी के लोग भी दहशत में आ गए हैं।

पाकिस्तान और चीन भारत के लिए खतरा

दोनों के कपटपूर्ण बर्ताव को अनदेखा नहीं किया जा सकता : नरवणे

स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए उच्च स्तर की लड़ाकू तैयारी

नयी दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और भारत के प्रति उनके कपटपूर्ण बर्ताव को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

जनरल नरवणे ने सेना दिवस से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख के हालात पर विस्तार से बात की और कहा कि भारतीय सैनिक किसी भी स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बहुत उच्च स्तर की लड़ाकू तैयारी रख रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि भारत और चीन परस्पर और समान सुरक्षा के आधार पर सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के लिए एक समझौते पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने वस्तुत: भारतीय सेना द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थिति कुछ रणनीतिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जा किये जाने का जिक्र करते हुए कहा कि सेना देश के हितों और लक्ष्यों के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में अपनी स्थिति कायम रखेगी। समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर जनरल नरवणे ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों की भारत के प्रति कपटपूर्ण सोच जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर गंभीर खतरा बने हुए हैं और उनकी कपटपूर्ण सोच से होने वाले खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत को दो मोर्चों पर खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान (शेष पृष्ठ 6 पर)

इस साल पांच प्रतिशत अधिक भरे गये आयकर रिटर्न

नयी दिल्ली। इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या करीब 5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गयी। ज्यादा संख्या में कंपनियों और इकाइयों द्वारा भरे गये रिटर्न के कारण आयकर रिटर्न की संख्या बढ़ी है। आयकर विभाग के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये 10 जनवरी 2021 तक 5.95 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किये गये। व्यक्तिगत तौर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 10 जनवरी तक थी, जबकि कंपनियों के लिये यह 15 फरवरी है। कर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि आकलन वर्ष 2020-21 के लिये 10 जनवरी 2021 तक 5.95 करोड़ आईटीआर भरे गये। वहीं पिछले आकलन वर्ष के लिये 10 सितंबर 2019 तक 5.67 करोड़ आईटीआर भरे गये थे। वित्त वर्ष 2019-20 के लिये कुल रिटर्न पिछले वर्ष के मुकाबले 33.5 लाख अधिक दाखिल किये गये।

राज्य में जल्द अस्तित्व में आयेगा युवा आयोग

स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर मुख्यमंत्री ने किया युवाओं से संवाद

- नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होंगे युवाओं के सुझाव
- स्वरोजगार अपनाकर अन्य को भी रोजगार दें राज्य के युवा

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वामी विवेकानन्द की 158वीं जयंती के अवसर पर आयोजित युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रदेश के कई युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आ जायेगा। इसके लिए बजट का प्रावधान हो चुका है।

उन्होंने कहा कि विवेकानन्द भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। उन्होंने पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से अवगत कराया। भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, यहां की संस्कृति में सबको साथ लेकर चलने की ताकत है। उन्होंने भारत की शौर्य, वीरगाथाओं और वसुधैव कुटुम्भकम की संस्कृति से दुनिया को अवगत कराया। दर्शन एवं साधक के रूप में हम विवेकानन्द के चरित्र को समझ सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी तरह की शक्ति हमारे युवाओं में होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विवेकानन्द ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं अगस्त्यमुनी के स्मरणों का वर्णन किया है। उत्तराखंड से स्वामी विवेकानन्द का विशेष लगाव था। उनका जीवन दर्शन युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के युवाओं के साथ जो संवाद हुआ, इसमें बहुत अच्छे सुझाव मिले। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि युवाओं ने जो भी सुझाव दिये हैं, उनका संग्रह किया जाय। ये विचार सरकार के लिए नीतिगत निर्णय लेने में सहयोगी हो सकते हैं। युवा जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कार्य के प्रति समर्पण का भाव हो तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। राज्य सरकार स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। युवाओं को रोजगार तक ही सीमित न रहकर अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ना होगा। स्वरोजगार के लिए राज्य में पर्याप्त संभावनाएं हैं। उत्पादों का वैल्यू एडिशन एवं प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, इस दिशा में और प्रयासों की जरूरत है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रोथ सेंटर पर कार्य किया जा रहा है। ग्रोथ सेंटर आज आजीविका बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार एडवेंचर टूरिज्म में रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक अलग विंग बनाई है। मुख्यमंत्री से युवाओं ने संवाद कर अपने अनुभवों को साझा किया। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से युवा कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, प्रदेश को और तेजी से प्रगति पथ पर ले जाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए और सरकार की योजनाओं के बारे में दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को जानकारी हो इस बारे में सुझाव दिये गये।

शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण था। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक विकासखंड में दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसका शासनादेश भी जारी हो गया है। इस शैक्षणिक सत्र से इनकी शुरुआत हो जायेगी। उत्तराखंड की खेल नीति जल्द प्रकाशित होने वाली है। उसके (शेष पृष्ठ 6 पर)